

(f) 1,30,000 K.W. @ 60 per cent. load factor.

Regional Coconut Research Station

2492. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a regional coconut research station in the Union Territory of Laccadive, Amindivi and Minicoy Islands;

(b) the total acreage of land under coconut crop in these Islands; and

(c) whether there is also proposal to start an elite seed garden on the Islands for coconut breeding?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) 6,000 acres.

(c) At the F.A.O. Conference on coconut held in Trivandrum during November-December, 1961 it was suggested that the possibility of starting an elite seed farm in the Laccadive Islands may be explored. Accordingly the Secretary, Indian Central Coconut Committee in his recent tour of the Islands investigated the possibilities regarding the above suggestion. He has reported that there is no vacant land for starting the Elite Seed garden in the Islands.

Grants to Y.M.C.As. and Y.W.C.As.

2493. Shri A. V. Raghavan: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to grant subsidies to the Y.M.C.As. and Y.W.C.As. of Kerala for providing western style facilities to middle class tourists; and

(b) if so, the centres chosen for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Government have under consideration a proposal to grant subsidies to the Y.M.C.As. and Y.W.C.As., for providing Western style accommodation facilities of a standard suitable for middle income group tourists. No decision has, however, been reached as yet and the centres where such subsidies should be given have not been finally selected.

दिल्ली और नरेला में बिजली का संभरण

२४९४. श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू कार्यों के लिये (१) दिल्ली, और (२) नरेला में बिजली प्रति युनिट दर क्या है ;

(ख) जब दोनों क्षेत्र एक ही कारपोरेशन के अधीन हैं, फिर दरों में विषमता के कारण क्या हैं; और

(ग) इस विषमता का सामाधान कब तक हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगेशान) : (क)

उपभोक्ता श्रेणी

१. घरों में प्रकाश के लिए बिजली तथा पंखे (Domestic Lighting and Fans)

२. घरेलू विद्युत (Domestic Power)

दिल्ली विद्युत संभरण उपकम नरेला

१८ नये पैसे प्रति युनिट । ६२ नये पैसे जल्दी अदायगी के लिए प्रति युनिट इसमें से ५ प्रतिशत कटौती कर दी जाती है

७ नये पैसे प्रति युनिट

३१ नये पैसे प्रति युनिट

(ख) यद्यपि नरेला दिल्ली नगर निगम के प्रोदेगिक अधिकार क्षेत्र में ही है, वहां पर विद्युत का उत्पादन, सम्भरण और वितरण एक प्राईवेट लाइसेंसदार नामक : राष्ट्रीय विद्युत सम्भरण तथा व्यापार निगम (प्राईवेट) लिमिटेड [National Electric Supply and Trading Corporation (Private) Ltd.] का उत्तरदायित्व है। दरों में अन्तर का कारण नरेला में विद्युत उत्पादन और सम्भरण का अधिक लागत होना है।

(ग) इस समय कोई भी तारीख नहीं बनाई जा सकती।

नरेला (दिल्ली) की गलियों में बिजली

२४६५. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला के दिल्ली नगर निगम के नागरिक नियंत्रण के अधीन आने के पहले भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेला द्वारा वहां मड़कों पर बिजली का प्रबन्ध था ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम द्वारा मड़कों से बिजली हटा ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). मड़कों पर लगी बिजली का साजसामान हटाया नहीं गया, बल्कि मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाइ एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राईवेट) लिमिटेड ने ७-६-१९६० से बिजली देना बन्द कर दिया क्योंकि भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति नरेला के साथ उनके करार की मियाद इस तारीख को खत्म हो गई। देहली नगर निगम ने मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाइ एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राईवेट)

लिमिटेड को बिजली बांटने का जो लाइसेंस दिया था वह मन्सूख कर दिया और हिदायत की कि साजसामान निगम के देहली बिजली प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन कम्पनी ने अदालत से निषेधाज्ञा (इन्जेक्शन) हासिल कर ली जिससे निगम पर यह रोक लग गई कि वह साजसामान न ले। सरकार अभी इस मामले का अन्तिम हल नहीं निकाल पाई है। अभी काम चलाने के लिये, निगम द्वारा मिट्टी के तेल से जलने वाले ८० लालटेन दे दिए गये हैं।

टेलीफोन के कॉल का किराया

२४६६. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) गाजियाबाद से दिल्ली और (२) नरेला से दिल्ली तक प्रत्येक सामान्य टेलीफोन काल का शुल्क क्या है ;

(ख) नरेला के लिये टेलीफोन काल की दरें ऊंची होने के कारण क्या हैं, विशेष रूप से जब कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और नरेला दिल्ली में; और

(ग) इन दरों में समता लाने के लिये क्या कार्यावाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगज्जबन राम) : (क) (?) स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क १२ न० पै०।

(२) तीन मिनट के सामान्य टेलीफोन काल के लिए ६० न० पै०।

(ख) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को डायल करके स्वयं टेलीफोन मिला सकता है और ऐसी कालों को ट्रंक टेलीफोन प्रचारकों द्वारा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नरेला की दूरी अधिक है और टेलीफोन कालों